जनसत्ता

कुपोषित विकास

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि एक ओर दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को पैमाना बना कर अलग-अलग देशों में विकास की चमकती तस्वीरें पेश की जा रही हैं और दूसरी ओर बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से मंगलवार को जारी बाल पोषण संबंधी रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है कि विश्वभर में पांच साल से कम उम्र के लगभग सत्तर करोड़ बच्चों में से एक तिहाई बच्चे या तो कुपोषित हैं या फिर मोटापे से पीड़ित हैं। नतीजतन, इन बच्चों पर पूरे जीन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त रहने का खतरा बना रहेगा। 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन' रिपोर्ट की ताजा तस्वीर विकास के दावों की हकीकत बताने के लिए काफी है। सवाल है कि अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों के बरक्स अगर दुनिया के एक तिहाई बच्चे किसी न किसी बीमारी की चपेट में अपनी जिंदगी काटेंगे तो उस चमक को किस तरह देखा जाएगा! विकास के प्रचारित पैमानों में अगर बच्चों के पोषण पर केंद्रित कार्यक्रम दुनिया के देशों की प्राथमिकता में शुमार नहीं हुए तो सेहत की कसौटी पर आने वाली पीढ़ियों के व्यक्तित्व का अंदाजा भर लगाया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम स्वस्थ खानपान की लड़ाई हार रहे हैं। असल में एक नई समस्या यह खड़ी हो रही है कि कहीं जरूरत से ज्यादा और असंतुलित खानपान की वजह से बच्चों का वजन अत्यधिक है तो किसी परिवार में बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। दोनों ही स्थितियों को कुपोषण के ही रूप में देखा गया है। एक में बच्चे मोटापे से पीड़ित हो रहे हैं तो दूसरे में बच्चों का कद अपनी आयु के मुताबिक काफी छोटा है और वे अत्यंत दुबलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। कुपोषण, भोजन में पोषण तत्त्वों की कमी और मोटापा एक ही साथ आसपास और यहां तक कि कई बार एक परिवार में भी देखा जा सकता है। जहां विश्वभर में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से करीब आधे बच्चों को भोजन में आवश्यक विटामिन और खनिज नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं लगभग दो अरब लोग हानिकारक खाद्य पदार्थों का जरूरत से ज्यादा सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते मोटापे, हृदय संबंधी और मधुमेह की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं।

जहां तक भारत का सवाल है, यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यहां हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। जबकि देश में हर साल एक लाख करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है, यानी चालीस फीसद भोजन वार्षिक उत्पादन में बेकार हो जाता है। जाहिर है, पोषण का यह असंतुलन खानपान की स्थितियों से जुड़ा है, लेकिन दरअसल यह असंतुलित विकास नीतियों का नतीजा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरी दुनिया को अगले दशक के आखिर तक भुखमरी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया है और संयुक्त राष्ट्र के इस लक्ष्य से भारत भी जुड़ा हुआ है। विकास के बरक्स व्यापक कुपोषण के विरोधाभास की यह हकीकत इक्कीसवीं सदी के उस दौर में भी कायम है, जब कई देश अपने सीमा-क्षेत्र में आम लोगों की जरूरतों और यहां तक कि बुनियादी समस्याओं से दो-चार होने के समांतर दुनिया में खुद को विकसित और ताकतवर देशों के साथ होड़ में होने का दावा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि विकास के पैमानों में वे सवाल हाशिये पर छोड़ दिए जा रहे हैं, जिनके नतीजों में एक बड़ी आबादी अपने बच्चों का पेट तक ठीक से नहीं भर पा रही है।

बेलगाम लुटेरे

दिल्ली में लूटपाट, झपटमारी की वारदात जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। राजधानी का शायद ही कोई इलाका ऐसा होगा जहां लुटेरों का आतंक न हो। सुबह, दोपहर, शाम हो या रात, झपटमार बेखौफ होकर अपने काम में लगे हैं। पिछले तीन-चार महीनों में तो ऐसे अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। घर के आसपास निकलने में भी लोग घबराने लगे हैं। इस तरह के अपराधों में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि लुटेरों पर दिल्ली पुलिस का कोई बस नहीं रह गया। बढ़ते अपराध कानून-व्यवस्था की रखवाली दिल्ली पुलिस को कठघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। तीन हफ्ते के दौरान ही तीन बड़ी वारदातों ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा संबंधी दावों की कलई खोल कर रख दी है। सोमवार रात बाइक सवार लुटेरों ने दिल्ली के कमला नगर इलाके में एक जज का मोबाइल छीन लिया। इसी दिन द्वारका इलाके में एक विमान परिचारिका की चेन छीन ली गई। इससे पहले पिछले महीने की पच्चीस तारीख को साकेत कोर्ट की एक जज का लुटेरों ने तीन किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पर्स छीन लिया था और भाग निकले थे। यह घटना सरिता विहार इलाके के पास की थी। लेकिन पुलिस हरकत में तब आई जब हाल में राजनिवास जैसे कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में प्रधानमंत्री की भतीजी के साथ लूटपाट की घटना हो गई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि लूटपाट, झपटमारी जैसी घटनाएं बढ़ने के पीछे बड़ी वजह युवाओं की बेरोजगारी और पुलिस की निष्क्रियता है। काम-धंधा नहीं मिलने से नौजवान आपराधिक गतिविधियों में जल्द शामिल हो जाते हैं और उन्हें कमाई का यही सबसे आसान जरिया लगता है। फिर, पुलिस की नजर में इस तरह के अपराध शायद कोई बड़े अपराध नहीं, आम बात हैं। पुलिस के इसी रवैये से चोरों-झपटमारों के हौसले बुलंद होते हैं। ज्यादातर मामलों में तो पुलिस लूट, झपटमारी के मामले भी दर्ज नहीं करती। आम आदमी तो इस तरह की घटनाओं की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। उसे पता होता है कि इस तरह की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस उसे किस कदर परेशान करेगी। जब पुलिस एक जज की लूटपाट की घटना को चोरी में दर्ज करने पर आमादा हो तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि आमजन के साथ क्या होता होगा। पिछले महीने सरिता विहार में जज के साथ लूटपाट की घटना के बाद यही हुआ था। पुलिस ने पहले चोरी की धारा में मामला दर्ज किया, लेकिन जज की आपत्ति के बाद उसे लूटपाट का मामला बनाया गया। इस मामले में पुलिस अभी तक किसी को नहीं पकड़ पाई है।

सवाल है लुटेरों के आगे पुलिस इतनी लाचार क्यों है? कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों में जगह-जगह अवरोधक लगे होने और पुलिस गश्त के बावजूद लुटेरे बिना हेलमेट के कैसे सड़कों पर घूमते और वारदात को अंजाम देते रहते हैं? अगर कैमरे न लगे होते तो प्रधानमंत्री की भतीजी को लूटने वाले पकड़ में ही नहीं आ पाते। पुलिस पर लापरवाही के आरोप इसलिए भी लगते हैं कि वीआइपी मामलों को सुलझाने की दर जहां पनचानबे फीसद है, वहीं आम लोगों से जुड़ी वारदात के मामले में यह दर मात्र पचपन फीसद है। ऐसे अपराधों को अंजाम देने वाले पेशेवर गिरोहों से जुड़े होते हैं, लेकिन जहां तक सजा का सवाल है, पुलिस और न्याय प्रणाली की जटिलता और सबूतों के अभाव में बहुत ही कम अपराधियों को सजा हो पाती है। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस मुस्तैद हो और जिम्मेदारी से काम करे तो इस तरह की वारदात पर अंकुश लग सकता है।

कल्पमेधा

मनुष्य को अंधविश्वासजन्य नैतिकता से मुक्त होना चाहिए।
- बर्ट्रेंड रसेल

बिखरते परिवार और बुजुर्ग

ज्योति सिडाना

आज ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का सबसे गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता।

सामान्य रूप में वरिष्ठ नागरिक की अवधारणा को तीन आयामों से समझा जा सकता है। पहला जैवकीय, अर्थात उसकी आयु के आधार पर, दूसरा मनोवैज्ञानिक अर्थात व्यक्तित्व में शामिल स्थिरता के आधार पर और तीसरा सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम यानी उनके अनुभवों के आधार पर। ये तीनों पक्ष किसी भी बुजुर्ग के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होते हैं। इसलिए ये समूह समाज के लिए एक उत्पादक इकाई बने रहते हैं। ये अपने अनुभवों को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से नई पीढ़ी को इस आशा के साथ हस्तांतरित करते हैं कि अगर नई पीढ़ी उनके अनुभवों को अपने जीवन में प्रयुक्त करती चली जाएगी, तो उनके जीवन के जोखिम या खतरे कम होते जाएंगे। इसी वजह से इन्हें परिवार का मुखिया माना जाता है और परिवार में इनकी प्रतिष्ठा उच्च होती है।

लेकिन अब प्रौद्योगिकी, संस्कृति और गतिशीलता में परिवर्तन के कारण परिवार नाम की संस्था की संरचना तेजी से बदल रही है। इस कारण बुजुर्ग अलगाव, अकेलेपन और पृथक्करण का शिकार हो रहे हैं। परिवार के कई सदस्य स्थानिक गतिशीलता के कारण घर से अलग दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार में जो भूमिका यह पीढ़ी निभा रही थी, वही भूमिका अब पालना घर जैसी बाजार की संस्थाएं निभा रही हैं। परिवार में अब बच्चों के समाजीकरण का काम अब बाजार या तकनीक करने लगी है। संभवतः यही कारण है कि बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक लगाव और सदस्यों के प्रति दायित्व की भावना नहीं पनपती। इसलिए ये पीढ़ी सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असुरक्षा का शिकार हो रही है। यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और निजी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में परिवार की भूमिका अब कम महत्त्वपूर्ण हो गई है। इसके लिए दोष किसे दिया जाए, यह एक चिंतन का विषय हो सकता है?

परिवार समाज की नींव होता है, क्योंकि यह सामाजिक संगठन की आधारभूत इकाई है। पूर्व के समाजों में परिवार विस्तृत नातेदारी का एक हिस्सा हुआ करता था, जबकि आधुनिक समाजों में परिवार नातेदारों और संबद्ध समुदायों से कट गए हैं। इसके परिणामस्वरूप भावनात्मक तनाव परिवार का एक आवश्यक, लेकिन नकारात्मक अवयव बन कर उभरा है। यह भी सच है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने परंपरागत परिवारों के सामने अनेक संकट उत्पन्न किए हैं, जैसे तलाक की दर में वृद्धि, सहजीवन (लिव-इन-रिलेशनशिप), एकल अभिभावक परिवार, एक व्यक्ति परिवार इत्यादि। संभवतः ये परिवर्तन व्यक्तिवाद के बढ़ते प्रभाव को व्यक्त करते हैं जो परंपरागत परिवारों को चुनौती देते नजर आते हैं। इन परिवर्तनों ने समाज में असुरक्षा, अस्थिरता, तनाव को बढ़ावा दिया है और अब ये परिवारों में भी प्रवेश कर चुके हैं।

आज ज्यादातर बुजुर्ग घुट-घुट कर जीवन जीने को बाध्य हैं। यह आज के उपभोक्तावादी दौर का सबसे गंभीर परिणाम है। इसलिए परिवार में भय और हिंसा के पक्ष भी उभरे हैं। मनुष्य के मध्य संबंधों में अविश्वास उत्पन्न हुआ है, वह अलगाव का शिकार है, क्योंकि अमानवीय परिवेश इतना सघन रूप धारण कर चुका है कि वह किसी से भी अपनी इच्छाओं को साझा नहीं कर सकता। देखा जाए तो एक तरफ तो समाज में स्वतंत्रता बढ़ी है, परंतु पहले की तुलना में व्यक्ति आज अधिक जकड़न में है क्योंकि उसके पास स्वाभाविक और स्वतंत्र जीवन जीने का समय ही नहीं बचा है। अविश्वास, धोखा, स्वार्थपरकता, भावनाओं का व्यवसायीकरण, प्रसिद्धि के द्वारा स्वयं को स्थापित करने की कोशिशें जैसे घातक पक्ष अब जीवन में शामिल हो चुके हैं। इसलिए वह इतना एकाकी है कि किसी पर भी भरोसा नहीं करता, उसकी आंतरिक शक्ति समाप्त हो चुकी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साल 2016 में देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ इक्कीस हजार से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराधों के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां ऐसे कुल चार हजार छह सौ चौरानवे मामले सामने आए। उसके बाद मध्यप्रदेश (3,877), तमिलनाडु (2,895) और आंध्र प्रदेश (2,243) का स्थान आता है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या एक सौ चार करोड़ थी, जिनमें इक्यावन करोड़ पुरुष और तिरपन करोड़ महिलाएं थीं। इनकी देखभाल के लिए सरकार और स्वंयसेवी संगठनों की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसकी उन्हें जानकारी भी नहीं होती। हाल के एक अध्ययन में सामने आया कि देश में पैंसठ वर्ष की आयु से ज्यादा के उनतीस प्रतिशत लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि इनके बच्चे या तो विदेश में रहते हैं या नौकरी की वजह से दूसरे शहरों में रह रहे हैं। इनमें से बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है। ऐसे में ये बुजुर्ग घर में अकेले रहने के दौरान या अकेले बाहर निकलते वक्त अपराधियों के लिए आसान निशाना होते हैं। बुजुर्गों के साथ तेजी से बढ़ रही अपराध की घटनाएं इसी ओर संकेत करती नजर आती हैं।

परंपरागत परिवारों में वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा सदस्य को भावनात्मक समर्थन मिलता था। जब घर का कोई छोटा सदस्य या बच्चा अपने पेशे या नौकरी में निराशा और तनाव का सामना करता था तो बुजुर्ग उसके लिए सुरक्षा का कवच बन कर खड़े हो जाते थे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य नई या युवा पीढ़ी के लिए एक परामर्शदाता की भूमिका निभाते थे। लेकिन तेजी से बदलते परिवेश ने उनकी इस भूमिका को हाशिए पर ला दिया है। समाज वैज्ञानिक मिशेल बैरेट तर्क देती हैं कि परिवार की अवधारणा में ऐसे तत्व भी होते हैं जो उसे समाज विरोधी बनाते हैं, क्योंकि यह महिलाओं के शोषण की वैधता को स्थापित करता है और परिवार के परिवेश के बाहर महिला के जीवन की किसी भी संभावना को समाप्त करता है। अतः परिवार के इस चरित्र को बदलने की आवश्यकता है।

देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का परिवार से घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था व्यक्तिवादी होती जा रही है, वैसे-वैसे परिवार में भी व्यक्तिवादिता का मूल्य बढ़ता जा रहा है। कृषि युग में संयुक्त परिवार थे, औद्योगिक युग में एकाकी परिवार, सेवा क्षेत्र के युग में एकल अभिभावक परिवार और डिंक परिवार (डबल इनकम नो किड्स) और उत्तर-औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एकल व्यक्ति परिवार अस्तित्व में आए हैं। परिणामस्वरूप समाज में सामूहिकता की समाप्ति या परिवार की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। जब परिवार संस्था ही समाप्ति के कगार पर खड़ी हो तो समाज या सामाजिक संघठन के विघटन को कैसे रोका जा सकता है? परिवार प्रणाली में होने वाले इस विघटन को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को परिवार में शामिल किया जाए, लैंगिक समानता को स्थापित किया जाए, लड़के-लड़की को समान शिक्षा और मूल्य दिए जाएं, परिवार में संबंधों में ऊंच-नीच जैसे भेदभाव को समाप्त किया जाए, प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे का सम्मान करे, तकनीक या सोशल मीडिया पर निर्भरता को कम करके परिवार के सदस्यों को महत्त्व देने, भौतिक वस्तुओं की तुलना में मानवीय संबंधों को अधिक महत्त्व देने जैसे प्रयास जरूरी हैं।

अगर परिवार मजबूत होता है तो समाज मजबूत होता है और समाज मजबूत होता है तो राज्य भी मजबूत होता है। राज्य मजबूत होता है तो अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति सभी व्यवस्थाएं मजबूत होती चली जाती हैं। किसी भी राष्ट्र का मजबूत और कामयाब होना उसकी परिवार प्रणाली की मजबूती पर निर्भर करता है और परिवार की मजबूती वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका पर आश्रित होती है। इसलिए इस विषय पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है।

सिकुड़ती दुनिया

पूजा यादव

दुनिया मेरे आगे

आसपास एक नजर डालें तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक बीमार समय में जी रहे हैं। काफी दिनों बाद एक संबंधी के जाना हुआ तो शुरुआती कुछ मिनट आपस में बातचीत के बाद वहां मौजूद करीब दस लोगों में से ज्यादातर की नजर अपने स्मार्टफोन में डूब गई। बीच-बीच में भले ही वे औपचारिकता के लिए हां-हूं कर देते थे, लेकिन उनका ध्यान मोबाइल की स्क्रीन में था। यहां तक कि बच्चे भी खेलने या बात करने के बजाय मोबाइल के स्क्रीन में कुछ देख कर हंस-खेल रहे थे। दरअसल, आजकल लोग अपने कामों में इतने अधिक व्यस्त हैं कि उनके पास ठीक से खाने-पीने तक का समय भी नहीं है। बच्चों पर गौर करें तो एक तरह से झटका लगता है, क्योंकि स्कूली और घर की पढ़ाई का बोझ उठा लेने के बाद बाकी वक्त वे स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते हैं। यों आजकल लोगों का लगभग हर काम घर बैठे फोन या लैपटॉप पर ही हो जाता है। मां-पिता बिना कुछ सोचे-समझे अपने बच्चों के हाथों में फोन थमा देते हैं, यह जानते हुए भी कि इससे बच्चों का भविष्य खराब होगा। न केवल पढ़ाई-लिखाई बाधित होने, बल्कि सेहत और बनते हुए मन-मस्तिष्क में एक परोक्ष बाधा खड़ी करने के लिहाज से भी। बच्चों का छोटी उम्र में फोन का बेलगाम इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे उनकी आंखें तो कमजोर हो ही सकती हैं, कई बार इंटरनेट पर मौजूद कुछ अवांछित सामग्री भी हैं जो अगर बच्चों की नजर में आ जाती है तो उन्हें अपनी जद में ले लेती है।

सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन इधर यह देखने में आ रहा है कि बच्चे अपनी पढ़ाई के बजाय अपना बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करने लगे हैं। थोड़ा बारीक नजर डालें, तब पता चलता है कि जब से सोशल मीडिया का प्रयोग बेतहाशा बढ़ा है, तब से हमारे चारों तरफ मानसिक बीमारियां भी बढ़ गई हैं। हर वक्त स्मार्ट फोन के स्क्रीन में डूबे रहना कब एक लत बन जाता है, हमें इसका पता भी नहीं चलता। स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताने के कारण आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आई हैं, जिनसे पता चलता है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया साइबर अपराध के लिए एक आसान जगह हो गई है। बच्चों की निजी जानकारियां, फोटो, वीडियो आदि चुरा लेना और उन्हें ब्लैकमेल करना या डराना-धमकाना एक आम बात होती जा रही है। ज्यादा उम्र के बच्चे और यहां तक कि उनके हमउम्र भी डराने-धमकाने के इस खेल में शामिल पाए जाने लगे हैं। इसके अलावा, युवा, अधेड़ और कई बार बुजुर्ग भी इसका शिकार होने से नहीं बच पाए हैं।

सच यह है कि इस तरह की व्यस्तता की वजह से सामाजिक जीवन में भी असहजता आई है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करने के बजाय शक करने लगे हैं। ऐसे तमाम मामले सामने आए, जिनमें सोशल मीडिया के मंचों पर फैली किसी गलतफहमी की वजह से दो लोग या समुदाय आमने-सामने खड़े हो गए। सच यह है कि गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रवाह सबको नुकसान पहुंचा रहा है। इनकी वजह से बच्चों का ध्यान पढ़ाई से निकल कर दूसरी बेमानी गतिविधियों की ओर जाने लगता है। इस ओर शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता कि आजकल के बच्चे घर से बाहर निकल कर एक भी खेल नहीं खेलते और न ही अपने बंधे-बंधाए दायरे से निकल कर नए दोस्त बनाते हैं। दोस्त के नाम पर सोशल मीडिया के संपर्क के दोस्त ज्यादा होते हैं और असल जिंदगी में कम। यह समझना मुश्किल नहीं है कि सोशल मीडिया पर विकसित हुए दोस्ती के संबंध कितने उपयोगी साबित होते हैं।

इन दिनों हम जब भी हम बाहर जाते हैं तो अक्सर बच्चों को आइसक्रीम, कुल्फी, पिज्जा, बर्गर आदि की ओर ही भागते देखते हैं। बच्चों ने अब स्वाद के लिए खाना शुरू कर दिया है और पौष्टिक खाना कम कर दिया है। बल्कि वे यह सोच कर तो खाते ही नहीं कि उनके लिए क्या पौष्टिक खाना है और किससे उनकी सेहत बेहतर होगी। बच्चों के माता-पिता भी उन्हें चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा वगैरह खिलाते हैं और उनके साथ खुद भी खाते हैं। यह समझने की जरूरत नहीं लगती कि ऐसा करना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वैसे भी खाने-पीने की चीजों में बहुत मिलावट की जाती है और स्वस्थ भोजन मिलना मुश्किल होता जा रहा है।

इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार या दूसरों की राह देखने के साथ-साथ अगर हम खुद ही पहल करें तो किसी साधन को अपने और इस दुनिया के लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसकी उपयोगिता को ही देखते हुए अब चुनाव जैसी लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए भी सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लिया जाने लगा है, क्योंकि आज यह संचार का सबसे अहम जरिया बन चुका है। दरअसल, सोशल मीडिया का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो इसके फायदे भी हैं। जरूरत बस इसे ठीक से समझने की है।

पराली का धुआं

इन दिनों दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए फिर से चेतावनी आई है कि पंजाब और हरियाणा से हर साल की तरह पराली का धुआं आना शुरू हो गया है। इन राज्यों में किसानों ने धान की फसल के अवशेष यानी पराली जलानी शुरू कर दी है। इससे राजधानी के दो सौ किलोमीटर तक दायरे में लोगों के लिए सांस तक लेना दूभर हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने तो हवा को शुद्ध रखने के लिए अगले महीने सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने के लिए ऑड-ईवन व्यवस्था फिर से लागू करने का एलान कर दिया है। हालांकि खेतों में पराली जलाना गैरकानूनी है, फिर भी किसान इस पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि किसानों के सामने भी मजबूरी है, उनके सामने पराली को नष्ट करने का कोई विकल्प या सुविधा नहीं है। अगर नहीं जलाएंगे तो अगली फसल कैसे लगाएंगे, यह बड़ी समस्या है। इसके लिए समाधान तो सरकारों को ही निकालना होगा। पराली जलाने से खेतों की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है।

● *घनश्याम गुप्ता, बलिया*

सरकारी लापरवाही

आखिर जिस चीज का डर था वही हुआ। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के खेतों में पराली जलाई जा रही है और उसका धुआं दिल्ली की ओर आ रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में मंडी गोबिंदगढ़, जलंधर, लुधियाना जैसे शहरों की हवा सबसे प्रदूषित आई है। पर अब सरकार के हाथ-पैर मारने और इस प्रदूषण को काबू करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब सरकार को सख्त होना चाहिए था, तब उसने सख्ती नहीं दिखाई। इसका नतीजा हम सब के सामने है। परंतु अब सरकार की प्रदूषित वायु को शुद्ध करने की गाड़ी आकर दीवाली के पटाखों पर रुकेगी। लेकिन क्या सिर्फ पटाखों को रोकने या उस पर समय का प्रतिबंध लगाने से वायु को साफ किया जा सकता है? अब सरकार यही कदम उठाएगी और ये भी भूल जाएगी कि तीन सौ पैंसठ दिन की समस्या को सिर्फ एक दिन के प्रतिबंध से काबू नहीं किया जा सकता।

● *जानवी बिट्ठल, जलंधर*

बेकाबू जुबान

हमारे नेताओं की जुबान कितनी बेकाबू होती जा रही है, इसकी ताजी मिसाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से देखने को मिली जब उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को 'मरी हुई चुहिया' कह डाला। इसके लिए खट्टर की जितनी निंदा की जाए, कम है। एक मुख्यमंत्री के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, क्योंकि वे एक राज्य के प्रमुख और प्रतिष्ठित पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजनीति में पक्ष-विपक्ष, विरोध-समर्थन सब होते हैं। मर्यादा में रह कर ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यह को पहला मौका नहीं है जब खट्टर ने इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया हो। वे पहले भी धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर की महिलाओं को लेकर बेसिर-पैर के बयान दे चुके थे। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं दिखाई। एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ एक महिला के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी करना निंदनीय है।

● *हेमा हरि उपाध्याय, खाचरोद, उज्जैन*

गांगुली से उम्मीदें

हाल ही में भारतीय क्रिकेट की शीर्ष संस्था बीसीसीआई में व्यापक स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। आमतौर पर बीसीसीआइ जैसी बड़ी स्वायतशासी संस्थाओं में चुनावों को बड़ी महत्ता दी जाती है, क्योंकि इस संस्था से बड़े पदों पर विराजमान मान्यवरों के हित जुड़े होते हैं। गांगुली का बीसीसीआइ अध्यक्ष के तौर पर चुने जाना उस पारदर्शिता में एक बड़ा कदम है जिसकी तलाश में स्वयं बीसीसीआइ, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति (सीओए) पिछले डेढ़-दो साल से लगी थी। गांगुली के कार्यकाल की अवधि मात्र दस महीनों की है और इस अवधि में उन्हें बहुत सारा फैला हुआ काम निपटाना है। इस श्रेणी में क्रिकेट तंत्र का नवीनीकरण और सभी राज्य क्रिकेट संगठनों को एक साथ एक ही राह ले चलना प्रमुख सुधार हैं। सौरव गांगुली भारत के सफलतम कप्तानों में गिने जाते हैं। अब देखना होगा कि वे भारतीय क्रिकेट में एक प्रशासक के रूप में दूसरी पारी कैसे खेलते हैं!

● *केशव शर्मा, राजस्थान विवि, जयपुर*

कड़ी कार्रवाई हो

भारत को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्विट्जरलैंड से स्विस बैंक खातेदारों का ब्योरा मिला है। यह एक अच्छी खबर है। यह ब्योरा देश के लिए तभी सार्थक हो पाएगा जब स्विस बैंक में काले धन जमा करवाने वाले भारतीय सफेदपोश लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दशकों से आम सुनने में आता रहा है कि भारत के बड़े बड़े चेहरों ने अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करवाया हुआ है, लेकिन अब हकीकत सामने आ गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि यदि कानूनी तौर पर संभव हो तो स्विस बैंक में पैसा रखने वाले भारतीय लोगों के नाम व उनके खाते में जमा राशि को जल्द से जल्द सार्वजनिक कर दिया जाएं और इस पैसे को देश में वापस लाकर गरीब लोगों की भलाई व विकास पर खर्च किया जाए।

● *राजीव शर्मा, कोटकपुरा, पंजाब*

जानलेवा गड्ढे

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने राजधानी भोपाल की सड़कों का निरीक्षण किया और पाया कि बरसात के कारण सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। उन्होंने पंद्रह-बीस दिन में सड़कों की मरम्मत की बात भी कही। बारिश के कारण केवल भोपाल की नहीं, पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढों से युक्त गई हैं। हाल में होशंगाबाद में सड़क के गड्ढों ने पांच होनहार हॉकी खिलाड़ियों की जान ले ली। इंदौर के मुख्य मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। लेकिन कोई देखने-सुनने वाला नहीं है। प्रशासन को चाहिए तत्काल सड़कों की मरम्मत करवाई जाए, ताकि जनता हादसों का शिकार न हो।

● *महेश नेनावा, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com